



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 516) पटना, बृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 जून 2013

सं0 22/नि0सि0(पट0)—03—04/2000/635—श्री रुद्र नारायण यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया को उक्त पदस्थापन अवधि में बरती गई कतिपय अनियमितताओं से संबंधित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0 264 दिनांक 25.9.2000 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1187 दिनांक 14.10.2000 द्वारा श्री यादव, कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित) के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री यादव को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गया:—

1. देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन वर्षों की रोक।
2. 10 (दस) हजार रुपये की वसूली।
3. निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु वेतनवृद्धि एवं पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जाएगी।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक 78 दिनांक 23.1.03 द्वारा संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए सरकार द्वारा जांच प्रतिवेदन से असहमति का बिन्दु देते हुए एवं उपरोक्त दण्ड के सरकार के निर्णय से अवगत कराते हुए श्री यादव से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री यादव से द्वितीय कारण पृच्छा से प्राप्त जबाब की सरकार के स्तर पर पुनः समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री यादव के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर विभागीय अधिसूचना सं0—844 दिनांक 22.7.03 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया:—

1. देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।
2. 10 (दस) हजार रुपये की वसूली।
3. निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन यापन भत्ता देय होगा तथा यह अवधि वेतनवृद्धि एवं पेंशनादि के प्रयोजनार्थ गणना की जाएगी।

उक्त संसूचित दण्ड के विरुद्ध श्री यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0—10720/04 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5.8.10 को पारित न्याय निर्णय में विभागीय अधिसूचना सं0—844 दिनांक 22.7.03 द्वारा संसूचित दण्ड को निरस्त कर दिया गया। उक्त की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरान्त उक्त दण्डादेश संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0 844 दिनांक 22.7.03 को विभागीय अधिसूचना सं0 821 दिनांक 7.7.11 द्वारा रद्द कर दिया गया।

तत्पश्चात् उक्त निर्णय के आलोक में श्री यादव द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 25.9.2000 से 22.7.03 तक को कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान के आदेश हेतु एक अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया।

उक्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-11(3) के आलोक में श्री रुद्र नारायण यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त के पक्ष में उनके निलंबन अवधि दिनांक 25.9.2000 से 22.7.2003 तक को कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतनादि भुगतान का निर्णय लिया गया है। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिए गए जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ते का समायोजन कर लिया जाएगा।

तदनुसार उक्त निर्णय श्री रुद्र नारायण यादव, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 516-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>